संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और जन-साधारण की सामाजिक सोच के अनुरूप ही निर्णय समाज को स्वीकार्य होते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) पीठासीन हुए]

महोदय, जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है। अतः सांसदों का जन-भावना के विपरीत निर्णय लेना अप्रजातांत्रिक है। जन-भावना के विपरीत कानून बनाने या न्यायालय में बयान/शपथ-पत्र देने से जनाक्रोश पैदा होता है, जोकि प्रजातंत्र में महंगा पड़ता है। ऐसे निर्णय कानून-व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। अतः यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस का भावी पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिन देशों ने इसे मान्यता दी है, उन्हें क्या लाभ/हानि हुई है? क्या इस से child abuse तो नहीं बढ़ेगा? क्या विदेशी समलैंगिकों का भारत अड्डा तो नहीं बन जाएगा? पारिवारिक और ग्रामीण जीवन तहस-नहस तो नहीं हो जाएगा? क्या सरकार का ऐसे विषय पर पक्ष लेना जरूरी है? अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि विभिन्न राजनीतिक दलों, धर्मों, के आचार्यों/नेताओं, प्रदेश सरकारों, पंचायती राज की इकाइयों आदि से राय प्राप्त कर आम सहमति बनाए बिना न कोई कानूनी संशोधन करे, न किसी न्यायालय में बयान/शपथ पत्र दे। महोदय, सदियों का चिंतन कानून द्वारा बदलना अनुचित होगा।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं स्वयं को डा0 राम प्रकाश के इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी सम्बद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, मैं भी सम्बद्ध करता हूं।

श्री नन्द कुमार साय (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी सम्बद्ध करता हूं।

श्री बी0एस0 ज्ञानादिशिखन (तमिलनाडु) : सर, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

Need to fill up the vacancies at National Library in Kolkata

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the National Library in Kolkata is the biggest library under the GoI system and the premier institution of the country. It is the seat of century old library tradition of India connecting its pre- and post-independence era. It is, therefore, necessary to maintain its glorious image by developing it further as a most modern library of international standard. But, unfortunately, it is now suffering due to its inadequate staff strength. Many of its sanctioned posts, numbering over 250, are lying vacant for long. A full-time Director for the library is also to be appointed. To continue its wide-spread routine work and users' service, as well as, to introduce many much-needed modern techniques of library services, it is urgently needed to fill up the vacant posts immediately. The situation and condition of the Central Secretariat Library, New Delhi, the second largest under the GoI system, is also the same, if not worse. I urge upon the Union Ministry of Culture to consider it seriously and take necessary steps immediately. Thank you.

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Dr. Barun Mukherjee.